(d) 500 to 600 lines per typist per day. Attention in this connection is invited to the reply against item (a) of Unstarred Question No. 2228 answered in the Lok Sabha on 15th June, 1971.

Statement

Month	Amount
	Rs. P.
January, 1972	3,726·65
February, 1972	3,580·10
March, 1972	5,459·05
April, 1972	4,202·65
May, 1972	4,532·50
June, 1972	4,387·85
July, 1972	1,402·65
August, 1972	2,853·75
September, 1972	2,412·55
October, 1972	2,738·25
November, 1972	3,742·95
December, 1972	4,128·20
	43,167·15

12 hours

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED INDEFINITE STRIKE BY THOUSANDS OF TEXTILE WORKERS IN DELHI

SHRI M. C. DAGA (Pali): I call the attention of the Minister of Labour and Rehabilitation to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

The reported indefinte strike by about twenty-seven thousand textile workers in Delhi.

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI RAGHUNATHA REDDY): Sir according to the information made available by the Delhi Administration, the employees in the five textile mills in Delhi, namely, (i) Delhi Cloth Mills, (ii) Swatantra Bharat Mills, (iii) D.C.M. Silk Mills, (v) Birla Cotton Spinning and Weaving Mills and (v) Ajudhia Textile Mills are on strike from April 11, 1973. The unions have put forward several demands. The main demand of all the workers relates to the enhancement of dearness allowance, and pending settlement of this issue, payment of an interim relief of Rs. 50 per month. The dispute regarding the adequacy of dearness allowance had earlier been referred by the Delhi Administration for adjudication, on the basis of a settlement signed on 26th February, 1970 by the Kapra Mazdoor Ekta Union, Textile Mazdoor Sangh and Kapra Mill Mazdoor Sangh and the managements of 4 textile mills. Later on, however, the unions raised objections about the maintainability of the industrial dispute regarding dearness allowance before the Tribunal. The Tribunal over-ruled the objections and held that Tribunal had jurisdiction to deal with the dispute regarding dearness allowance. The unions then filed a writ petition in the Delhi High Court. The Delhi Administration has stated that the matter is still pending as the stay granted by the High Court continues.

Following the recent strike notices by the unions, the Industrial Relations Machinery of the Delhi Administration has been holding discussions with the parties. Shri Bahl, Executive Councillor has also held several discussions with the workers' and employers' representatives in an effort to promote an amicable settlement. A proposal put forward by the Industrial Relations Machinery of the Delhi Administration was (a) 5 per cent. increase in emoluments by way of an interim relief, and (b) arbitration of the dispute by Shri Hidayat Ullah retired Chief Justice of the Supreme Court. The proposal was, however, not acceptable to the workers who

wanted a minimum interim relief of Rs. 30 per month and the same was not acceptable to the employers.

The Central Government feels deeply concerned about this strike. The Delhi Administration who as the "appropriate Government" are directly concerned, are seized of the matter and are continuing their efforts to bring about an early settlement. I understand that Shri Bahl has already held several discussions with the parties on April 13, 14 and 16, 1973. The Chief Labour Commissioner (Central) is also helping the Delhi Administration to resolve the dispute. The latest information is that Shri Bahl and employers' representatives are going to meet today evening at 5 p.m. to discuss this matter further

श्री मूल चन्द डागा . अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सेंटेंस याद आता है कि "जो नैतिक मान्यताओं के मध्य रहते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं ऐसे संघर्ष के प्रति उदासीन नहीं रह सकते जिसमे मानवता और सभ्यता की सर्वोच्च मान्यतायें दाव पर लगी हुई हो।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आप को इसलिये धन्यवाद देता हू कि आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाने का अवसर दिया है। 27,000 मजदूर आज सात दिन से बेकार हैं और उनकी अपनी एक माग है कि जो आपने सविधान में बात कही थी कि हम ऐसे शोषण विहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं और जगह जगह आपने यह बात कही कि देश के अन्दर हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें विषमता नही होगी। लेकिन मैं उस भूमिका को सामने रखते हुए आप से पूछना चाहता हूं कि 7 दिन होने के बाद भी हम लोग मजदूरों की सही मांगों को भी पूरा नही करा पाये। मजदूरो ने यह बात रखी थी, पहली उन की मांग यह थी कि उन्हें कम से कम 300 रु० मासिक वेतन दिया जाय, प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम 300 रु० दिया जाय। दूसरी मांग यह थी कि उस के रहने के लिये मकान दिया जाय, और अगर मकान नही दिया जाय तो उसे 20 प्रतिशत मजदूरी के रूप मे भत्ता दिया जाय। और तीसरी माग यह थी कि महगाई भत्ता इतना हो कि वह महंगाई को सम्हाल सके और ठेके पर लगाने की मजदूरो की पद्धति को समाप्त किया जाय। य चार उनकी मागे थी, और उन्होंने यह सवाल उठाया कि बम्बई और अहमदाबाद मे मजदूरो को जो कुछ मिल रहा है दिल्ली वालो को उन से कम नही मिलना चाहिये। यह प्रश्न अब दिल्ली के 27,000 मजदूरो का प्रश्न नही रहा बल्कि 672 टैक्सटाइल मिलो का प्रश्न बन गया है जिसमे 9 लाख 41 हजार टैक्सटाइल मजदूर काम करते हैं। उनका सवाल है कि बम्बई के अन्दर जो दिल्ली के मजदूर से 64 रु० ज्यादा मिलता है वह दिल्ली के मजदूरो को भी मिलना चाहिये। दिल्ली के मजदूर यह भी कहते हैं कानपुर, जो 'बी' श्रेणी में आता है वहां के मजदूरो को भी दिल्ली के मजदूरो से 22 रु० ज्यादा मिलता है।

जब कभी सरकार अपने कानून से आगे नही बढती और धीरे धीरे चलती है तो मजदूर समाज में उन शोषण करने वालो के खिलाफ़ बगावत होती है, उसके विरोध में अपनी आवाज बुलन्द करता है। जब कोई प्रथा सड़न की अवस्था मे पहुंच जाती है तो जनता में उस प्रथा के खिलाफ़ जनमत खिलाफ़ हो जाता है और हमारा कर्त्तव्य होता है कि ऐसे क

[श्री मूलचन्द डागा]

बनाये जाय जो समयानुसार हों, बदलते हुए जमाने के साथ कानून को बदलना होगा। यदि आप कानून की बारीकियो को लेकर मजदूरों के हित को धकेलना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि मजदूर उसके खिलाफ आवाज उठायेगा। दिल्ली के मजदूरों की माग है कि उन्हें 300 रु० मासिक वेतन मिलना चाहिये। उन्होने कहा कि कानपुर के मजदूरों से हमें 22 रु० कम क्यों मिलता हैं, उन्होंने कहा कि बम्बई के मजदूर की तुलना में हम 64 रु० कम लेने को तैयार बहो हैं। आप देखें कि बम्बई म कितनी बार रिवाइज हुआ उनका वेतन स्तर? समझ में नही आता कि जब आप लोगों को दुनिया में बताना चाहते हैं, हमने कहा है कि हम शोषण विहीन समाज चाहते हैं, हम मजदूरों को आगे बढाना चाहते हैं और जब मजदूर आगे बढना चाहता है तो उसको कानून की बारीकियों से आप रोकना चाहते हैं, यह कहा तक न्याय सगत है। कानून तो एक मकडी का जाला है जिसमे गरीब फसता है और धनवान छूट जाता है।

मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया उससे कोई बात स्पष्ट नहीं होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और जब मजदूर उस दिशा मे बढ़ने के लिये आवाज उठाता है तो कानून की बारीकियों का सहारा लेकर उसके कदमों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। आज कुछ लोग शायद कहेंगे कि 22 लाख रुपये दिल्ली के मजदूरो को जो मिलने चाहिये थे वह नुकसान हो रहा है, या कुछ लोग यह समझते होंगे कि हड़ताल की वजह से उत्पादन में नुकसान हो रहा है, और माननीय चव्हाण साहब यह समझते होंगे कि सवा लाख रुपये रोज के उत्पादन-कर का नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश के उत्पादन के नाम पर मजदूरों को भूखे रहने के लिये वायदे करना किसी भी तरह उचित नहीं है। अगर आपने उत्पादन के नाम पर मजदूरो को भूखे रखने का निर्णय ले लिया है तो इसको मजदूर लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मजदूरों का कदम आगे बढ जाता है तो वह पीछे कभी नहीं हटता है। देश में इनकलाब लाने के लिये दो कौमें हैं, एक मजदूर और दूसरे विद्यार्थी, और जब मजदूर अपनी सही बात कहता है और पूजीपतियो में उसके प्रति उदारता नही है, जिन्होने उसका शोषण किया है, तो बगावत होना स्वाभाविक हो जाता है।

आपने जापान की तनख्वाह का हाल देखा होगा। जापान ने यह किया कि ज्यो ज्यो मजदूरों की तनख्वाह बढ़ायी त्यो त्यो वहा उत्पादन बढा। देश को आगे बढाया। मैं आप को कुछ आकड़ बतलाना चाहता हूं

" ..if one considers that wage increases have gone up successively by 12.1 per cent in the year 1967, by 13.3 per cent in 1968, then by 15.6 per cent in 1969, and now finally by 17.5 per cent"

वहा के एम्प्लायीज कहते है कि उनका उत्पादन भी बढ़ना चाहिये और उनकी मजदूरी भी बढनी चाहिये। वहा के मालिक लोग भी यही चाहते हैं। आप लोग अपने देश मे एक अच्छी नीति कायम करना चाहते है। आप ऐलान करते हैं कि हम एक डीसेंट लिविंग देना चाहते हैं। आप की घोषणा यह है कि .

"The right to work under humane conditions and a living wage sufficient to assure a decent standard of life."

आज मजदूर लोग इसी के लिये आवाज उठा रहे हैं। कुछ पहले श्री बालगोविन्द वर्मा ने अपने एक भाषण में कहा था कि :

"Inaugarating the first meeting of the Central Advisory Contract Labour Board at New Delhi on June 14, 1972, the Union Deputy Labour Minister, Shri Balgovind Verma, called for total abolition of the contract labour system or, in the alternative, its control and regulation, in view of the present, alarming conditions of contract labour in unorganized industries where no trade unions are functioning."

मैं जानना चाहता हूं कि आपने इन दोनों नीतियों के बारे में क्या किया ? आपने वेतन नीति के मामले में क्या किया ? जब 1972 में सीमेंट उद्योग के मजदूरों ने हड़ताल की थी तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आश्वासन दिया था कि वर्ष के अन्त तक हम एक राष्ट्रीय वेतन नीति कायम करेंगे। 1972 के बाद योजना मन्त्री, श्री धर ने श्री चक्रवर्ती को मुकर्रर किया इस काम के लिये। लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि मजदूरों की पगार क्या है। वह तो ऊपर की मंजिल में बैठते हैं, 2,000 रु० तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने कह दिया कि मजदूरों के वेतन के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति 40 रु० मासिक व्यय का आधार मान लिया जाये। मैं कहना चाहता हूं कि इससे मजदूरों के अन्दर असन्तोष पैदा होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार की नीति में फर्क क्या हो गया है ? पहले श्री खाडिलकर साहब थे और अब श्री रघुनाथ रेड्डी आ गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को जरा तेजी के साथ चलना चाहिये। बदलते हुए जमाने के साथ कानून को भी बदलना चाहिये।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने सात दिन के भीतर क्या किया ? सात दिनों से 27,000 मजदूर अपने हकों के लिये लड़ रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए आपने खुद जाकर मजदूरों से बात करके उनको समझाया या नहीं ? एक प्रश्न तो मेरा यह है।

आज अध्यक्ष महोदय ने मुझ को इजाजत दी कि मैं इस सामाजिक प्रश्न को यहां उठाऊं। अगर इसके लिये संघर्ष किया जाये तो पार्लियामेंट का प्रत्येक सदस्य इस संघर्ष में मेरे साथ है क्यों कि मजदूरों के साथ उनकी सहानुभूति है। जब, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझ को मौका दिया है तब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन सात दिनों के अन्दर श्री रेड्डी ने मजदूरों के नुमाइन्दों से बात की ? क्या उन्होंने साहसपूर्ण शब्दों में उन लोगों से कहा कि पूंजी पतियों के दिन अब खत्म हो गये ? जो यह पूंजीवादी प्रथा है उसके खिलाफ कई आन्दोलन मजदूरों के अन्दर हुए। मैं कहता हूं कि इस प्रथा को बदलो। इस प्रथा के रहते हुए न हम किसी को न्याय दे सकते हैं और न किसी को मदद कर सकते हैं। क्या मन्त्री महोदय चाहते हैं कि यह प्रथा चलती रहे और मजदूरों का जीवन सुखी न हो ? क्या मन्त्री महोदय इन सात दिनों के अन्दर मजदूरों के बीच में गये और उनसे कहा कि तुम्हारी मांगों के बाबत हम यह कदम उठा रहे हैं ? जहां तक बम्बई के कारखानों का सवाल है, मजदूरों के कानून समय समय पर रिवाइज होते रहते हैं। लेकिन आप उस स्थिति को पहुंचना नहीं चाहते। (व्यवधान)

[श्री मूलचन्द डागा]

आज मजदूरों को, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहिये। आप को अपने पुराने कानून को बदलना चाहिये। आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को लेकर चल रहे हैं जो कि बाबा आदम के जमाने का कानून है। यह कानून आखिर आपको कब तक मदद करेगा? इसको पलटो, एक दिन मे पलटो, एक घंटे मे पलटो, इसी वक्त पलटो। अगर इसको नही पलटा जाता तो इस मजदूरों को कोई मदद नही मिलती।

मन्त्री महोदय ने कहा कि हमने बहल साहब को भेजा है 27,000 मजदूरो के साथ बात करने के लिये। मैं जानना चाहता हूं कि बहल साहब काम करेंगे या श्री रघुनाथ रेड्डी करेंगे? आप थोडी सद्भावना से काम लीजिये। आपने सात दिनो के अन्दर ठेकेदारी प्रथा की बाबत और मजदूरो की मागो की बाबत कोई सक्रिय और ठोस कदम नही उठाया। इसके न उठाने के कारण उत्पादन कम हो रहा है। लेकिन मुझे उत्पादन का उतना दु:ख नही है, मजदूरो को भूखा रखना उचित नही है। अगर समाज को आगे बढाना है तो मजदूरो को ठीक वेतन देना होगा, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति करनी होगी। जब मजदूर को उचित मजदूरी मिलेगी तो उत्पादन भी ज्यादा बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा।

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I am in full agreement with the philosophical part of the statement made by the hon. Member.

As far as the settlement of the dispute concerned, the industrial relations machinery of the Delhi Administration, which is the appropriate authority to deal with this matter and it is already seized of the matter. I have also brought to your kind notice that Mr. Bahl who is in charge of this on behalf of the Delhi Administration has met the persons concerned on the 13th, 14th and 16th and this evening he is expected to meet the representatives of the employers and have further discussion in the matter. I also had discussion with Mr. Bahl and we have placed the good offices of the Chief Commissioner of Labour who is an officer of the Central Government at the disposal of the Delhi Administration to deal with this matter. I assure the hon. House that I will intervene at the appropriate time if my services are required.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, he is naming somebody who is not here in this House to defend himself. Mr. Bahl is not here to defend himself Why is he taking his name?

MR. SPEAKER: I am very happy that you have become a defender of absentees.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): This strike which has now entered its seventh day, has once again brought sharply into the limelight, the basic question which is not a new one but which has been plaguing the workers of this country, in the textile and other industries, for several years and that question is one to which we expect some clear reaction from the Labour Ministry on behalf of the Government of India.

That question is this.

(I) It is not disputed by anybody that there is a phenomenal rise in prices. Even in the short period which has passed since the presentation of the last Budget, a price rise to the extent of 15 per cent or more has taken place, even in this capital city of Delhi—a rise which has affected even those items of consumption on which no excise duties or taxes were placed and we were assured that there would be no reason for any rise in prices of

those untaxed commodities. Nevertheless, such are the market operations under the blessings of this Government that there has been a rise in all these items.

So, firstly, the actual real wages of the workers have suffered a decline already. The real wages have gone down already. This is a common feature which is taking place over the years in many industries in most parts of the country. Secondly, there is the cost of living index figure which is compiled by the Labour Bureau whose office is in Simla. Times without number the central trade union organisations in this country have stated emphatically at the Indian Labour Conference and other forms that they have no confidence whatsoever in the way in which these cost of living figures get compiled by that Labour Bureau. It is done in a defective way, in a partisan way. It is done in such a way that the actual extent of rise is not at all reflected. The hon. Minister knows very well that the question of the very basis of this compilation of the cost of living figure was taken up by the workers in Bombay, Gujarat and other places and a strike was threatened on that very issue. A special Committee had to be set up to go into the thing, to find out the way in which those figures were being compiled, and that Committee came to the conclusion that some revision was necessary in the actual procedure of compilation Otherwise workers were being defrauded of the dearness allowance to which they are rightly entitled on the basis of the actual rise. But what we find is that the same old procedure is still continuing.

Then, thirdly, the workers are demanding a dearness allowance which gives them 100 per cent compensation for rise in the cost of living. I would like to ask the Minister whether he considers this demand to be unjustified. All that the workers say is that the existing real wages should be maintained and should not be reduced at all. It does not mean rise in wages at all. All it means is only compensation for the rise in the cost of living so that their actual real wages are not eroded but that they will be maintained at that same level. This is what their demand is. This is why the strike has taken place. There may have been some slight difference between some of the unions on the actual date of such strike. But I want to make it quite clear that all the Unions in Delhi representing the textile workers without exception are united on this question and this is their unanimous demand and they are united on the question of strike. The persons whom we are confronting are not employers who have not got the capacity to pay. After all, who are these persons? They are the largest monopoly houses, one is the House of the Birlas the other belong to the Shri Ram Group. They are the main employers with whom the workers have to contend with in this struggle. And, I was told, a few days ago, at the beginning of the strike, these employers had conveyed that they were willing to give an increase of Rs. 12 per month. Now, I am told, in the subsequent negotiations they had gone back even on those commitments and said that they had never offered any such thing and now they are not prepared to give any rise at all. This is the position. The workers have proved by facts and figures that unless 100 per cent neutralisation is given by way of DA, their real wages are getting eroded and will be further eroded. Traditionally the wage in the Delhi textile mills used to be higher than that of Kanpur. But recently, as the Minister knows, there was a strike in Kanpur and there was intervention by the UP State Minister, Mr. Ganesh Dutt Bajpai, and an *ad hoc* increase of Rs. 35 per month was given to the Kanpur workers. But, as a result of that increase now, I do not say, this was adequate, the Kanpur workers are getting more than Delhi workers, although Delhi workers were traditionally higher paid than the Kanpur workers.

[Shri Indrajit Gupta]

In such a situation, how do you assume that discontent will not crop up? Is this not sufficient justification for the strike? At the moment the workers are just on the streets. They cannot be told, your case will go to arbitration, adjudication, and all that. The Minister may stick to his routine reply and say that the appropriate authorities are looking into the matter. There is this gentleman Mr. Bahl in respect of whom the workers have got all kinds of opinions and have no confidence in him.

And then the Central Labour Commissioner has been added. I would just say that in a serious situation like this where the textile industry is closed down; where prodution of lakh of metres of cloth is being lost everyday there one does not always take shelter behind the technical niceties of the law in the sense as to who is the appropriate authority and who is not the appropriate authority. In such a matter many a time Labour Ministers have themselves personally intervened. They had called conferences, meetings, etc. at top level and taken some initiative to break the deadlock and bring about a settlement on the basis of the justified demands of the workers. Am I to take it that this Sriram Group and Birla Group are pleading financial incapacity? These are some of the biggest mills in the country. If these mills are not in a position to increase the dearness allowance of these workers so as to compensate them for the rise in the cost of living, then I would humbly suggest that a thorough probe should be ordered into the financial administration of these companies to find out how they are handling their finances and if necessary, these mills should be taken over.

I hope the Minister is not under any illusion. May be reports have been given to him that the strike is likely to fizzle out. I would only say there is no chance of the strike fizzling out. On the other hand, it will become a prolonged trial of strength, which is not good for anybody. Workers do not go on strike for fun. Therefore, I would request the hon. Minister to assure the House that he will not stick to the niceties of the Industrial Disputes Act but in view of the seriousness of the crisis he will take the initiative to break the deadlock and see to it that the monopoly tycoons of these textile mills are compelled to accept the legitimate demands of the workers so that an early settlement is brought about.

SRI RAGHUNATHA REDDY: Sir, I would very respectfully submit to you that I do not have any illusions about any matter. I do not suffer from any illusions. As far as this matter is concerned, the Central Government is seriously concerned with what is happening and about the strike. This evening Mr. Bahl who is incharge of Labour is meeting the representatives of the employees for holding further discussions Discussions were held on 14th, 15th and 16th and some negotiations were going on. This evening the representative of the Delhi Administration is meeting the employers for this purpose. I am just watching the development. As I have already said, whatever necessary action is called for would certainly be thought of but the hon. Members should give some time to the Delhi Administration.

(Interruptions)

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I assure you that I am second to none in this House in appreciating the anxiety and also the difficulties of the workers I do not want to say anything more because negotiations are going on.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: There cannot be any point of order during the Question Hour or calling-attention-notice. I am not permitting him.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I have not completed my answer. In Bombay, a worker gets Rs. 281 while

in Delhi he gets Rs. 226 and so there is a difference of about Rs. 55 or so. The wages are certainly higher in Bombay than in Delhi. But this is not something now. This is known already.

I may also state in this connection, that there were various settlements after reference to a tribunal on adjudication and so on, and the matters were taken to the High Court and the High Court had given a stay order. I do not want to go into the merits of the matter. The High Court's stay order is continuing. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: The hon. Member knows the rule. I am not permitting any hon. Member whose name is not there. No other Member can ask any question. I am not permitting him. He is speaking without my permission. Let him not interrupt.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: No new facts have been given by the hon Member ..

MR. SPEAKER. The hon Minister may please kindly sit down, because I have not allowed the hon. Member.

Now, Shri S. P. Bhattacharyya.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: The Member whose name is not on the Order Paper cannot ask any question.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: By writing to me, he does not become entitled.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I had understood the hon. Minister to say that he had not completed the reply to my question.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: As far as the figures are concerned, there is nothing new about them. Everybody knows about them. There is a difference of about Rs. 55 or so in the wages of a textile worker in Bombay and that of a textile worker in Delhi. The matter is being negotiated, and by the evening, I expect that some developments might take place.

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : दिल्ली में जो हड़ताल चल रही है 12 तारीख को यह विषय इस सदन के सामने लाया गया था और उसी समय हम अपेक्षा वह करते थे कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देकर और इस विषय मे सदन को भी विश्वास मे लेकर कुछ जानकारी और तथ्य सामने रखते। क्योंकि 27 हजार मजदूर इस तरह बेकार होकर और अपने काम से हाथ धोकर बैठ जायं, यह बात तो मैं समझता हू कि मन्त्री महोदय भी उचित नही समझेंगे । किन्तु मवाल यही है जैसा मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने आज की बढती हुई महगाई की स्थिति को सामने रखा, उसको देखते हुए क्या मन्त्री महोदय इस बात को उचित समझते हैं जैसे अभी उन्होने स्वयं स्वीकार किया कि बम्बई मे जितना वेतन मिलता है और दिल्ली मे जितना वेतन मिलता है उसमे अन्तर है, तो मजदूरों ने जो मांगे सामने रखी हैं क्या मन्त्री महोदय उसको जायज समझते हैं या नही, इसका मैं कैटेगोरिकल रिप्लाई मन्त्री महोदय से चाहता हूं । जो बातें हम सामने रखते हैं उनका सीधा सीधा जवाब मिल जाय तो कोई कठिनाई न हो । मजदूरो ने जो मागे सामने रखी ह उसमे कान्ट्रेक्ट लेबर की बात है, यह ठेके पर काम करवाने की पद्धति रेलवे में भी चलती है जिस के विरोध में कई बार हम यहां आवाज उठाते हैं, तो जब मजदूर भी इसके विरोध मे आवाज उठाते है तो क्या मन्त्री महोदय इसको उचित मानते हैं या नही वेतन में जो असमानता है उस असमानता को दूर करने के लिए जब वह अपनी उचित मांग को लेकर सामने आते हैं तो उनका न्याय का

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

पक्ष लेकर मन्त्री महोदय क्या करना चाहते हैं यह भी हम जानना चाहते है । जैसे अभी मेरे मित्र ते बताया कि शिमला मे बैठ कर लेबर ब्यूरो जो अपना काम करता हैं वह हम जानते हैं होलसेल प्राइस को लेकर वह करता है हाला कि सामान्य मजदूर का होलसेल प्राइस से कोई वास्ता नही होता है, उसका रिटेल प्राइस से वास्ता होता है । इसलिए हमेशा उन का असली वेतन मारा जाता है । इसलिए उन की जो असली माग हैट सेपरसेट न्यूट्रलाइजेशन की, जितनी महगाई बढती है उतना उनको मिले और असली वेजेज उनकी बढे नही, क्या इस बात को मन्त्री महोदय उचित समझते है या नही ? यदि वह इस को उचित समझते है तो मैनेजमेट के साथ बैठ कर इतने दिनो से उन्होंने क्या किया यदि है मैनेजमेट उनकी उचित मागो को मानने के लिए तैयार नही हैं तो मैनेजमेट को मनवाने के लिए आप क्या करने जा रहे है

और भी एक बात मैं पूछना चाहता हू । जैसे मेरे मित्र ने बनाया कि इसमे सभी यूनियने है । कोई भी यूनियन ऐसी नही है जो इस हडताल मे शामिल नही है ।

(व्यवधान) इसलिए मैं बडी निष्पक्षता से बात कर रहा हू

My assessment is an objective assesment, not subjective like that of Shri Indrajit Gupta or of Shri Jyotirmoy Bosu (*Interruptions*)

Mr SPEAKER Order, order May I tell Shri Bosu that none of the observations of members who are not permitted by me will come on record? Only the remarks of members whose names appear on the list will come on record. Why do you interrupt and fight against each other when you know that they do not mean anything?

श्री जगन्नाथराव जोशी मै तो यही कहना चाहता था कि मेरी यूनियन न होने के बाद भी जायज मागे है मजदूरो की इसलिए मैं उसके समर्थन के लिए खडा हुआ हू । इसलिए मैं ने कहा कि माई असेसमेंट ज एन आब्जेक्टिव असेसमेंट और इसलिए मैं यह बार-बार पूछ रहा हू कि आप समानता की बात करते है और असमानता जब मत्री महोदय स्वीकार करते है तो उसको दूर करने के लिए अपनी मागो को लेकर मजदूर जब सामने आते है तो इतने दिनो से मत्री महोदय ने क्या किया ? और सभी यूनियने इसमे शामिल है जैसे मेरे मित्र ने बताया कि कोई आगे करने वाली थी कोई पीछे करने वाली थी लेकिन इस बात मे सब एक मत थे कि हडताल हो । इस सबध मे मै एक बात और कहना चाहता हू कि क्या प्रेस्टिज का प्वाइट बना कर इटक के साथ ही बैठ कर समझौता करे या न करे ऐसा तो नही है या जो भी इसमे शामिल है उन सभी यूनियनो के प्रतिनिधियो के साथ बैठ कर सरकार इसका हल जल्दी से जल्दी निकलवाने की कोशिश करेगी ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY As far as the demands are concerned, the Indian National Trade Union Congress has championed the cause of the workers in respect of these demands. As far as the difference between the Bombay and Delhi wages is concerned, I have already stated that there is a difference between the Bombay and Delhi wages (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Mr. Bosu, please do not do it. No question of submission now.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: All these matters are under discussion between the representatives of the employees and the employers and also the Delhi Administration, and as I submitted, at 5 O'clock this evening, we expect something... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: He does not allow you to speak. I have already told Shri Bosu that he is not allowed to speak.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: There is a procedure laid down for it.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Jagannath Mishra.

Mr. Bosu, you know the procedure. Knowingly you come and you are doing it deliberately. I am very sorry; I do not approve of it.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: If you do not allow, may I stop it? You are interrupting. Please sit down.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Why are you interrupting on a motion which belongs to others?

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Do not talk like that.

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, कानून और नियम का काम है शान्ति स्थापित करना, लेकिन शान्ति तब तक स्थापित नहीं हो सकती है जब तक कि वह सोशल-जस्टिस के आधार पर न हो। अभी आइ०एन०टी०यू०सी० के झण्डे के नीचे 27 हजार मजदूरों ने हड़ताल की है—और यह सब उसी का दुष्परिणाम है। जहां दिल्ली की टैक्सटाइल मिलों में काम करने वाले मजदूर कम पाते हैं, वहां दूसरे बड़े शहरों में टैक्सटाइल मिलों में काम करने वाले मजदूर बहुत ज्यादा पाते है, इसी लिए यहां के मजदूरों मे असतोष और आक्रोश की भावना स्वाभाविक है और फलतः उन्होने स्ट्राइक का निर्णय लिया है।

मैं स्ट्राइक के सम्बन्ध में बहुत कह कर समय नही लूगा, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि इस स्ट्राइक को सभी का समर्थन प्राप्त है, हर पार्टी का, हर व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है। मैं सरकार से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं और इस उम्मीद से कि सरकार का ध्यान उधर जाये और वह इस हडताल को हटवाने, तुड़वाने में पहल करे। इस प्रसंग में मेरा पहला प्रश्न है—

1. क्या यह सही नही है कि मजदूरों और उनके परिवारों को भोजन, कपड़ा और जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए पूर्णतः मजदूरी पर निर्भर करना पड़ता है—इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें नीडबे-स्ड-मिनिमम वेज दिया जा रहा है ?

2. गत बार जब उनकी मजदूरी निर्धारित हुई, उस वक्त सामान के मूल्यों में और आज के सामान के मूल्यों में कितने परसेन्टेज का अन्तर है ?

3. क्या दिल्ली से बाहर के मजदूरों को ज्यादा मजदूरी दी जा रही है और यहां

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

के मजदूरों को कम दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या उनका ज्यादा के लिये मांग करना युक्तिसंगत नहीं है ? यदि युक्तिसंगत है तो दिल्ली प्रशासन इस स्ट्राइक को हटाने के लिये और मजदूरों की मांगों की पूर्ति की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

4. सुना जाता है कि स्ट्राइक के पूर्व कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि और मिल-मालिको के प्रतिनिधि तथा दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधि मिले थे और उनकी आपस में बातचीत भी हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों में किन-किन मुद्दो पर सहमति हुई और जिन मुद्दो पर असहमति हुई उनके निवारण के लिए क्या किया जा रहा है ?

आज स्ट्राइक का सातवां दिन है, 27 हजार मजदूर भूख से मर रहे है, उनकी स्थिति चिन्ताजनक हो रही है। इस विषय को लेकर बड़ी चिन्ता की भावना व्याप्त है। इसलिए मै केन्द्रीय सरकार से आग्रह करूगा कि इस स्ट्राइक को तुड़वाने और मजदूरो को उनका हक दिलवाने में सरकार शीघ्र कार्यवाही करे।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूगा कि टैक्सटाइल मिलो में जो मशीन पर काम करने वाले मजदूर है, रुई का अंश और अन्य गन्दगियां उनके शरीर के भीतर जाने के फलस्वरूप व तपेदिक से बीमार हो जाते हैं और उनकी असमय में मृत्यु हो जाती है, उनका जीवन दुखमय हो जाता है। अब भूखि स्ट्राइक चल रही है और यह मानी हुई बात है कि यह स्ट्राइक कल-परसों में टूटेगी, जब सुलह की बात चल रही है तो क्या उन गरीबों की दशा पर भी अलग से विचार किया जायेगा तथा उनकी दशा को सुधारने के लिए सरकार कुछ करेगी ? दिल्ली एक यूनियन टैरिटरी है, इसलिए इस विषय के निवारण के लिए सरकार इस पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: It is true that the INTUC is leading the strike... (*Interruptions*) C.I.U. C.I T.U., A.I.T.U.C. and other unions are also in the strike. The strike is total. Government are deeply concerned over this matter... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Do not intervene. I have not permitted any Member now.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: Government are deeply concerned about the welfare of the workers. I do hope that all the concerned parties would appreciate the deep anxiety of the Government for finding a proper and just solution in this matter.

As for the points raised by Mr. Jagannath Mishra, I have already made a statement. It is true that there are differences in Delhi, Bombay and Kanpur. All these matters can be taken up. At 5 O'clock the representatives of employees as well as employers are meeting; the Delhi Administration is taking action... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: The hon. Minister has replied. I cannot force the hon. Minister to state what the hon. Members like. Papers to be laid.... (*Interruptions*).